

प्रेषक,

डॉरणबीर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग—1

देहरादून : दिनांक 8 दिसम्बर, 2011

विषयः—उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय निकायों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—399 / श0वि0नि0—विविध—44(वेतनमान) / 2006 दिनांक 02 जून, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या—877 / XXXVII(7)च0श्रो / 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 एवं आदेश संख्या—07 / XXVII(7)27(V) / 2011 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय निकाय के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों हेतु निम्नवत् लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1—दिनांक 01.01.2006 से पूर्व समूह “घ” के वेतनमान ₹ 2550—3200, ₹ 2610—3530 तथा ₹ 2650—4000 के पदों पर दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड—1 के एस, ₹ 4440—7400 तथा ग्रेड वेतन क्रमशः ₹ 1300 /—, ₹ 1400 /— एवं ₹ 1650 /— के स्थान पर वेतन बैण्ड—1 ₹ 5200—20200 एवं ₹ 1800 /— के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण दिनांक 01.01.2006 से कात्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च, 2011 से वास्तविक लाभ/नकद भुगतान किया जायेगा।

2—समूह “घ” के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जायेगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह “घ” के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹ 1900 /— का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹ 1900 /— वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

3—समूह “घ” के ग्रेड पे ₹ 1300 /—, ₹ 1400 /— एवं ₹ 1650 /— के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जायेगा, जहाँ पर ग्रेड पे ₹ 1800 /— के पद कम पड़ते हैं (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहाँ पर उस सीमा तक ग्रेड पे ₹ 1300 /—, ₹ 1400 /— एवं ₹ 1650 /— के पद ₹ 1800 /— के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जायेंगे।

4- ₹ 1800/- की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह “घ” के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्थाप्त समाप्त होते जायेंगे अर्थात् समूह “घ” के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹ 1800/- ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह “घ” के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जायेंगे।

5- उक्त उच्चीकरण के फलस्वरूप होने वाले व्ययभार का वहन संबंधित निकाय स्वयं अपने संसाधनों से करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या- 565 / XXVII(7) / 2011 दिनांक 05.12.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉरणबीर सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या /२६३ / IV(1)/01(21)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा०शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढवाल / कुमायूँ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त जिलाधिकारी।
- 8- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)।
- 9- प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)  
उप सचिव।